किस्म की धान बेची है उस मूल्य और 350 रुपये प्रति क्विंटल के बीच के अन्तर की राशि खरीफ मौसम, 1993-94 के लिए एक बार तदर्थ बोनस के रूप में अदा की जाएगी। प्रारंभ में पंजाब सरकार द्वारा जांच-पड़ताल करने के बाद किसानों को भुगतान किया जाएगा और उसके बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

पंजाब में विपणन मौसम, 1993-94 के दौरान सरकारी वसूली एजेन्सियों द्वारा अब तक (29-1-1994 तक) लगभग 12.00 लाख मीटरी टन मूल्य-44 धान की वसूली कर ली गई है।

Closure of Sugar Mills in Madhya Pradesh

3364. SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA : Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what are the details and the number of sugar mills in Madhya Pradesh which are closed as on date ;

(b) what are the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to restart the production in these mills ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) AU the eight sugar factories in Madhya Pradesh have worked during the current 1993-94 sugar season (October—September).

(b) and (c) Do not arise.

खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार

3365. श्री मूलचन्द मीणा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास खाद्यान्नों का कितना सुरक्षित भंडार था; और

(ख) खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार बनाए रखने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) 30 नवम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का स्टाक निम्नानुसार था :

(लाख मीटरी टन)
1-12-1993

चावल	91.99
गेहूं	120.36
जोड़	212.35

(ख) खाद्यान्नों का पर्याप्त बफर स्टाक बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार भारतीय खाद्य निगम और उनके एजेन्टों के रूप में राज्यों के खाद्य विभागों तथा उनकी एजेन्सियों के जरिये मूल्य समर्थन योजना के अधीन खाद्यान्नों की वसूली करती है। सरकार के पास इस समय खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति काफी सुगम है और 1-1-1994 की स्थिति के अनुसार यह स्टाक बफर स्टाक रखने के लिए निर्धारित किए गए मानदण्डों से भी अधिक है।

Profits/Losses of the CWC

3366. SHRI G. PRATHAPA REDDY: Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) what are the profits or losses of the Central Warehousing Corporation for the last three years;

(b) whether Government feels that the said corporation is still necessary in view of the changed policy towards the PSU ; and"

(c) if so, what steps are being taken by Government in this regard?